सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन तथा लाभ में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विविधीकरण तथा उत्पाद-मिश्र, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, तथा संयंत्र-मशीनरी का आधुनिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

औद्योगिकरण का विरोध

658. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः**
श्री राज मोहिन्दर सिंहः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "मेनका अपोज्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश का औद्योगिकीकरण करने के स्थान पर पारंपरिक संस्कृति व उद्योगों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से देश का विकास करने की योजना को प्राथमिकता देनी चाहिये; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करने और एक आधुनिक एंव दूरदर्शी भारत का निर्माण करने के लिए लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे समाज का निर्माण तब ही किया जा सकता है जब यदि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के अंग के रूप में विकास करे, न कि अलग रहकर। अतः सरकार आधुनिक तथा परंपरागत उद्योगों के विकास की नीति इस प्रकार अपना रही है, जो कि देश से समग्र हित में होगी।

Industrial growth Centres in U.P.

659. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of industrial growth centres functioning in Uttar Pradesh;

(b) the details of the funds provided to these growth centres during each of the last three years;

(c) whether any study has been made of the impact of these growth centres in terms of generating employment opportunities in U.P. in general and its backward areas in particular; and

(d) if so, th details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) Under the Growth Centre Scheme seven growth centres have been approved by the Central Government for execution in Uttar Pradesh by the State Government of U.P. None of the growth centres has become fully functional yet. The details of release of funds to these centres are given in the attached statement. (*See* below)

(c) and (d) No study has been made by the Central Government of the impact of these growth centres in terms of generating employment opportunities.

Statement

Total release of Central assistance towards the seven approved growth centres at Bachauli Buzurg, Banthara, Chaudharpur, Dibiapur, Khurja, Mungra-Satharia and Sahajanwa is Rs. 2080 lakh.

During the last three years, funds have been released to the following to the extent shown against each:

Name of the growth centre	Amount released (Rs. in Lakh)		
	1995-96	1996-97	1997-98
Khurja (Bulandshahr	200	—	170